www.jagran.com राष्ट्रीय संस्करण
दैनिक जागरण
शुक्रवार 3 मई 2019

दैनिक जागरण
श्रम किए बिना प्राप्त संपदा फलीभूत नहीं होती

आसानी से नहीं मानेगा पाक

पाकिस्तान में पल रहे आतंकी संगठन जैश ए मुहम्मद के सरगना मसूद अजहर पर अंतरराष्ट्रीय पाबंदी लगना भारत की एक बड़ी कूटनीतिक कामयाबी है। यह कामयाबी हासिल करने में एक दशक इसीलिए लग गए, क्योंकि चीन इस आतंकी सरगना की ढाल बना हुआ था। उसने अपना अड़ियल रवैया तब छोड़ा जब उसके सामने यह स्पष्ट हो गया कि भारत इस मामले को छोड़ने वाला नहीं और अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस आदि देशों के चलते उसकी अंतरराष्ट्रीय स्तर पर फजीहत हो सकती है। इसमें दोराय नहीं कि भारत ने एक बड़ी कूटनीतिक कामयाबी हासिल की, लेकिन यह भी स्पष्ट है कि पाकिस्तान तमाम शर्मिंदगी उठाने के बावजूद अपनी हरकतों से बाज आने वाला नहीं। संसद और पठानकोट एयरबेस समेत पुलवामा में आतंकी हमलों के लिए जिम्मेदार मसूद अजहर पर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की पाबंदी लगने के बावजूद आसार इसी के हैं कि पाकिस्तान भारत के लिए खतरा बने आतंकियों को पालने-पोसने की अपनी नीति का परित्याग न करे। अंदेशा इसका भी है कि वह मसूद अजहर पर उसी तरह की दिखावटी सख्ती करे जैसे उसने एक अन्य आतंकी सरगना हाफिज सईद के खिलाफ कथित तौर पर कर रखी है। आखिर यह एक तथ्य है कि पाकिस्तान सरकार और खासकर उसकी सेना एवं खुफिया एजेंसी आइएसआइ अपने यहां फल-फूल रहे आतंकियों के खिलाफ कुछ न करने और दबाव पड़ने पर कार्रवाई का दिखावा कर अंतरराष्ट्रीय समुदाय की आंखों में धूल झोंकने में माहिर है। हैरत नहीं कि पाकिस्तानी सेना मसूद अजहर को और संरक्षित करने का काम करे।

पाकिस्तान पर इसलिए भरोसा नहीं किया जा सकता, क्योंकि उसने यह कहकर अपनी झेंप मिटाने और साथ ही अपनी जनता को भरमाने की कोशिश की है कि मसूद अजहर पर पाबंदी के बावजूद उसकी जीत हुई, क्योंकि सुरक्षा परिषद के फैसले में पुलवामा हमले का जिक्र नहीं है। पाकिस्तान के ऐसे रवैये को देखते हुए यह जरूरी है कि भारत और अमेरिका इसके लिए अतिरिक्त कोशिश करें कि पाकिस्तान वास्तव में मसूद अजहर पर लगाम लगाए। अगर वह ऐसा नहीं करता तो फिर उसकी चालबाजी के पुख्ता सुबूत एकत्र करके उन्हें एफएटीएफ के समक्ष रखने चाहिए। इस अंतरराष्ट्रीय संस्था की अगली बैठक में इस पर विचार होना है कि पाकिस्तान को आतंकी संगठनों को पालने के लिए काली सूची में रखा जाए या नहीं? पाकिस्तान पिछली बैठक में काली सूची में जाने से बच गया था। अगली बार भी चीन उसके बचाव में आ सकता है। यदि पाकिस्तान काली सूची में दर्ज होने से फिर बच जाता है तो वह आतंकी संगठनों को संरक्षण देने का काम तेज कर सकता है। चूंकि पाकिस्तान के रंग-ढंग बदलने की ज्यादा उम्मीद नहीं इसलिए भारत को उसकी हरकतों को लेकर न केवल सतर्क रहना होगा, बल्कि उस पर यह दबाव भी बढ़ाना होगा कि वह आतंकवाद का सहारा लेना छोड़े। निःसंदेह इसी के साथ ऐसे भी उपाय करने होंगे जिससे पाकिस्तान कश्मीर में दखल देने में सक्षम न रहे। यह ठीक है कि पुलवामा हमले के बाद कश्मीर के हालात ठीक करने के लिए कई कदम उठाए गए हैं, लेकिन यह भी साफ है कि अभी बहुत कुछ किए जाने की जरूरत है।

आय में इजाफा

उत्तराखंड सरकार अपनी आय के संसाधन बढ़ाने को हाथ-पांव मार रही है। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने राज्य में आमदनी के स्रोत बढ़ाने और राजस्व प्राप्ति से जुड़े मुहकमों के लिए महीनेवार राजस्व का लक्ष्य निर्धारित करने को कहा है। आमदनी कम और खर्च ज्यादा बढ़ने के मर्ज से जूझ रही सरकार को चालू वित्तीय वर्ष के पहले महीने में ही बाजार से कर्ज उठाने को मजबूर होना पड़ा है। राज्य के कुल सालाना बजट का बड़ा हिस्सा सिर्फ वेतन-भत्तों, मानदेय, पेंशन आदि पर खर्च हो रहा है। हालत यह है कि विकास संबंधी अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए कुल बजट का महज 13 फीसद भी नसीब नहीं हो पा रहा है। यही वजह है कि विषम भौगोलिक क्षेत्रों में जहां विकास कार्यों पर तुलनात्मक रूप से ज्यादा धनराशि खर्च होती है, वहां विकास की रफ्तार बेहद धीमी है। ढांचागत सुविधाओं के विस्तार और इन सुविधाओं की गुणवत्ता में सुधार अथवा प्रति व्यक्ति आय एवं सकल घरेलू उत्पाद जैसे आर्थिकी के आंकड़े पर्वतीय क्षेत्र में फिसड्डी बने हुए हैं। इन क्षेत्रों में सामाजिक-आर्थिक विषमता की खाई चौड़ी हो रही है। समान रूप से विकास की अवधारणा पर आगे बढ़ने के लिए राज्य सरकार को वित्तीय संसाधनों में वृद्धि की दरकार है, लेकिन हालत उलट है। अपने संसाधनों में इजाफा करने के बजाय सरकार सिर्फ केंद्रीय योजनाओं में मिलने वाली मदद के भरोसे है। साल-दर-साल केंद्रीय योजनाओं पर निर्भरता बढ़ रही है, जबकि खुद के संसाधन बढ़ाने में इच्छाशक्ति की कमी बड़ा रोड़ा बनी है। राज्य सरकार अपने संसाधन बढ़ाकर केंद्रीय योजनाओं के दायरे से बाहर रहने वाले क्षेत्रों में भी विकास की प्रतिपूर्ति कर सकती है। उत्तराखंड में कुटीर उद्योग-धंधों, पर्यटन के साथ ही सहकारिता एवं खेती आधारित उद्योगों के विकास की व्यापक संभावनाएं हैं। ये क्षेत्र आमदनी के साथ ही आजीविका और रोजगार के लिहाज से भी अहम हैं। इसके लिए मजबूत इच्छाशक्ति के साथ आगे कदम बढ़ाने की जरूरत है।

आतंक के खिलाफ बड़ी सफलता

विवेक काटजू

भले ही पाकिस्तान मसूद अजहर के खिलाफ कोई कार्रवाई न करे जैसा कि उसने हाफिज सईद के मामले में दिखाया तब भी उस पर पाबंदी भारत की बड़ी कामयाबी है

मसूद अजहर के अंतरराष्ट्रीय आतंकी घोषित होने के साथ ही यह तय हो गया कि चीन जैश ए मुहम्मद के इस सरगना की ढाल नहीं बनेगा। चीन कई वर्षों से उसे बचाता आ रहा था, मगर आखिरकार उसने अपना रवैया बदला। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के बाकी सदस्य देशों की मसूद अजहर को अंतरराष्ट्रीय आतंकी घोषित करने की मुहिम में चीन ने अतीत में कई बार अड़ंगे लगाए। अजहर पर बदला रुख चीन की नीति में बड़ा बदलाव है, क्योंकि हाल में और यहां तक कि पुलवामा आतंकी हमले के बाद भी उसने मसूद अजहर का बचाव किया था। पुलवामा हमले के बाद अमेरिका द्वारा प्रवर्तित और फ्रांस एवं ब्रिटेन द्वारा समर्थित संयुक्त राष्ट्र के प्रस्ताव पर चीन ने अवरोध पैदा किया। इस प्रस्ताव का मकसद मसूद अजहर को अंतरराष्ट्रीय आतंकी घोषित करना था। मार्च के मध्य में उसने अमेरिकी प्रस्ताव में तकनीकी पेच फंसाकर इस प्रक्रिया को टाल दिया। ऐसा करते हुए चीन 2009 से चली आ रही अपनी नीति पर कायम था। यह समझना होगा कि चीन ने अपने दृष्टिकोण को आखिर क्यों बदला और भारत एवं मोदी सरकार के लिए इसके क्या मायने हैं?

पुलवामा हमले की जिम्मेदारी खुद जैश ए मुहम्मद ने ली थी। यह भारतीय सुरक्षा बलों पर सबसे जघन्य हमला था जिसने पूरे देश की चेतना पर करारी चोट की थी। समूचा देश इससे आक्रोशित था। 2016 में उड़ी हमले के बाद भारत द्वारा की गई सर्जिकल स्ट्राइक से प्रधानमंत्री मोदी ने स्पष्ट कर दिया था कि पाकिस्तान की ओर से होने वाले आतंकी हमले का भारत केवल राजनीतिक एवं कूटनीतिक दायरे में रहकर ही जवाब नहीं देगा। बालाकोट हमले के साथ अंतरराष्ट्रीय जगत को भी स्पष्ट रूप से यह संकेत दे दिया गया कि आतंकवाद के खिलाफ भारत की नीति बदल गई है और अब उसका रणनीतिक धैर्य जवाब देता जा रहा है। बालाकोट हमले के बाद संयुक्त राष्ट्र में मसूद अजहर को घेरने का अमेरिकी प्रस्ताव इसका परिचायक था कि भारत का आक्रोश वाजिब है। अनौपचारिक रूप से उसने स्वीकार भी किया कि भारत को अपनी आत्मरक्षा का पूरा अधिकार है। अमेरिका और अन्य पश्चिमी देश पाकिस्तान को यह संदेश देना चाहते थे कि वह अब आतंकी खेल खेलना बंद करे, क्योंकि भारत अब उसके खिलाफ सैन्य कार्रवाई करने से नहीं हिचकेगा।

इससे यही जाहिर होता है कि पहले जहां भारत पर आतंकी हमले के बाद धैर्य बनाए रखने का दबाव होता था वहीं अब उस पर आतंकी हमले रोकने के लिए दबाव बढ़ गया है। पाकिस्तान के साथ अपने हितों को देखते हुए चीन संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में अमेरिका के प्रस्ताव का समर्थन करने का अनिच्छुक था। पुलवामा हमले के तुरंत बाद अमेरिका ने सुरक्षा परिषद में हमले की निंदा करने वाला प्रस्ताव पारित कराने का भी प्रयास किया। तब भी चीन ने उसमें अड़ंगा लगाया। चीन के अड़ियल रवैये से आजिज आकर इस प्रस्ताव का समर्थन करने वाले अमेरिका सहित अन्य देश मसूद अजहर को अंतरराष्ट्रीय आतंकी घोषित करने का प्रस्ताव सुरक्षा परिषद की समिति में ले आए। इस प्रस्ताव पर चीन और ज्यादा कुपित हो गया। ऐसा इसलिए, क्योंकि सुरक्षा परिषद की समिति में जब किसी आतंकी का मसला उठता है तो उस आतंकी को केवल तकनीकी आधार पर ही नहीं बचाया जा सकता। उस देश को सार्वजनिक रूप से उस आतंकी की करतूतों का भी बचाव करना पड़ता है। इससे अलग-थलग पड़ने के साथ ही अंतरराष्ट्रीय शर्मिंदगी झेलने का जोखिम भी बढ़ जाता है।

अवधेश राजपूत

भारत ने संयुक्त राष्ट्र में अपने काबिल विशेष दूत सैयद अकबरुद्दीन की अगुआई में खामोशी के साथ, लेकिन सही कूटनीतिक पत्तों के साथ अपनी चाल चली। इस बीच चीन ने अमेरिका के प्रस्ताव को मार्च तक किसी तरह लटका दिया। बाद में यह मामला अमेरिका और चीन के बीच फंस गया। चीन ऐसे संकेत दे रहा है कि वह दुनिया की महाशक्ति के रूप में अमेरिका को चुनौती देना चाहता है। वहीं ट्रंप इस चुनौती की हवा निकालने को आतुर हैं। अमेरिका और उसके समर्थक देश फ्रांस और ब्रिटेन ने चीन से कहा कि वे इस प्रस्ताव को परिषद के सामने लाने के लिए दृढ़संकल्पित हैं ताकि उसके दोहरे चरित्र को बेनकाब कर सकें।

बीते कुछ हफ्तों से चीन इसी दुविधा से जूझता रहा कि क्या वह ऐसा आभास कराना चाहता है कि पाकिस्तान के साथ उसके हित इतने ज्यादा जुड़े हुए हैं कि उसके लिए वह मसूद अजहर को लेकर अपनी अंतरराष्ट्रीय छवि भी दांव पर लगा सकता है जिसके तार पाकिस्तानी फौज से भी जुड़े हुए हैं? हाल में पाकिस्तानी प्रधानमंत्री इमरान खान ने द्वितीय बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव समिट में भाग लेने के लिए चीन का दौरा किया। चीन ने उन्हें तवज्जो देते हुए चीन-पाकिस्तान आर्थिक गलियारे यानी सीपैक को लेकर उनसे व्यापक समर्थन मांगा। यह इस बात को दिखाने की कोशिश थी कि पाकिस्तान के साथ चीन के हित दिनोंदिन मजबूत होते जा रहे हैं। इससे मसूद अजहर पर चीन के रुख में आए बदलाव से पाकिस्तानी जनता में उपजे आक्रोश को कुछ हद तक शांत करने में मदद मिलेगी। पाकिस्तान में तमाम लोग यही सोचते रहे कि पाक के साथ अपने रिश्तों को देखते हुए मसूद अजहर के मामले में चीन कभी भी पाकिस्तान को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर शर्मसार नहीं होने देगा। हालांकि पाकिस्तानी नीति निर्माता चीन से अभी भी इसी अपेक्षा में लगे थे कि वह भारत में चल रहे चुनावों के बाद ही यह कदम उठाए, क्योंकि अभी ऐसा करने से भाजपा चुनावों में इस मुद्दे को भुना सकती है। ऐसा लगा भी कि चीन इसी राह पर है, लेकिन अमेरिकी दबाव और भारत में मोदी की वापसी की संभावना को देखते हुए उसे अपना रुख बदलना पड़ा।

चीन के रुख में बदलाव भारत के लिए निश्चित रूप से एक बड़ी कूटनीतिक कामयाबी है, क्योंकि वह बीते कई वर्षों से मसूद अजहर को अंतरराष्ट्रीय आतंकी घोषित कराने के लिए प्रयास कर रहा था। भले ही पाकिस्तान अजहर के खिलाफ कोई कार्रवाई न करे जैसा कि उसने हाफिज सईद जैसे आतंकी के मामले में किया, तब भी इस आतंकी सरगना पर पाबंदी भारत के लिए एक बड़ी सफलता है। मसूद अजहर के अंतरराष्ट्रीय आतंकी घोषित होने से भाजपा को स्वाभाविक रूप से एक मुद्दा मिल जाएगा जिसका वह चुनाव अभियान में भरपूर लाभ उठाना चाहेगी। अजहर का मामला भारत-चीन संबंधों के लिए भी एक सबक है। चीन तब तक भारत की चिंताओं पर गौर नहीं करता जब तक कि बड़ी शक्तियां उस पर इसके लिए दबाव नहीं डालतीं। वर्ष 2008 में परमाणु आपूर्तिकर्ता देशों के समूह में भी ऐसा ही हुआ था। तब अमेरिकी राष्ट्रपति बुश द्वारा भारत के मुखर समर्थन के बाद ही चीन के तेवर ढीले पड़े थे। इस मामले में भी यही देखने को मिला। स्पष्ट है कि वुहान जैसी भावना से ज्यादा अंतरराष्ट्रीय हितों के साथ संयोजन अधिक आवश्यक है।

(लेखक विदेश मंत्रालय में सचिव रहे हैं)

response@jagran.com

येती के बहाने सेना पर निशाना

तरुण विजय

कुछ आलोचक ऐसी प्रतीति करा रहे मानो सेना ने येती के पदचिन्ह देखने का दावा सरकार के कहने पर किया हो

खुद को लिबरल और सेक्युलर बताने वाले लोग कोई ऐसा मौका और मुद्दा नहीं छोड़ते जिसका सहारा लेकर वे आग्रही भारतनिष्ठों पर आक्रमण न करें। इन्हें कभी हमने नक्सली हिंसा में शहीद होने वाले जवानों को श्रद्धांजलि देते हुए अथवा नक्सली और जिहादी हिंसा का निषेध करते हुए मुश्किल से देखा होगा। महाराष्ट्र से लेकर छत्तीसगढ़ तक नक्सली आतंकी सुरक्षा बलों के जवानों और नागरिकों की हत्याएं करते हैं, लेकिन तथाकथित सेक्युलर लोग नक्सलियों को गरीबों के हक में लड़ने वाले क्रांतिकारी बताते नहीं थकते। ऐसे लोग भारतीय सेना के एक दल द्वारा हिमालय की उंचाइयों पर येती के पदचिन्ह देखने के दावे पर उसका मजाक उड़ाने से भी नहीं चूके। इस बहाने वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर चोट करते हुए एक तरह की तृप्ति और आनंद महसूस करते दिखे। ऐसा लगा कि मानो सेना ने येती के पदचिन्ह देखने का दावा प्रधानमंत्री के कहने पर किया हो।

आज तक किसी झोलाछाप क्रांतिकारी और जंतर मंतर पर हर रोज डेरा लगाए रहने वाले बयान बहादुरों को हमने नक्सली आतंकवादियों, पुलवामा हमले के अपराधी जिहादियों या पूर्वोत्तर के अलगाववादियों के खिलाफ न तो प्रदर्शन करते हुए देखा और न ही जैश और लश्कर जैसे आतंकी संगठनों के विरोध में एक शब्द भी लिखते या बोलते देखा। खुद को सेक्युलर बताने वाले इन लोगों की आवाज उठती है तो केवल उन आग्रही भारतनिष्ठों के विरुद्ध जो तिरंगे की शान और संविधान के मान के लिए जान कुर्बान करने को तैयार रहते हैं। हाल तक इन सेक्युलर तत्वों का आधिपत्य हर बौद्धिक एवं अकादमिक संस्थानों, मंत्रालय, हर फेलोशिप और सरकारी अनुदानों के स्रोत पर छाया हुआ था। एक समय तक नियम यह था कि जिस सामान्य कर्मचारी तक की पृष्ठभूमि में भगवा दिखे उसे प्रताड़ित कर या तो हटा दिया जाए या नियुक्ति के समय ही उसे खारिज कर दिया जाए। नुरूल हसन से अर्जुन सिंह तक यही चला। इस विशेषाधिकार संपन्न गिरोह में शामिल होने के लिए जरूरी था कि आप रोमिला थापर और इरफान हबीब पढ़ें और उनके लेखन से सहमत भी हों। इसी के साथ यह भी जरूरी है कि आप भगवा के खिलाफ बोलें और बहुसंख्यकों पर हमले के लिए शब्द हिंसा का सहारा ही न लें, बल्कि उन वाम विचारों को महत्व दें जो भारत से तो गायब हो रहे हैं और अब जिनके खंडहर भी देखने को नहीं मिलते। इसके विपरीत यह भी अपेक्षा की जाती है कि आग्रही भारतनिष्ठों के विचार प्रतिबंधित ही रखे जाएं, भले ही संपूर्ण भारत में उनका समर्थन एवं उनके विचारों को पढ़ने वालों की संख्या बढ़ रही हो। ऐसा वैचारिक नाजीवाद सोवियत रूस या कम्युनिस्ट चीन में हो तो समझ आता है, पर भारत में लोकतंत्र का ही सहारा लेकर भिन्न विचारों को प्रतिबंधित करना यह सेक्युलर नाजीवाद का भारतीय संस्करण ही कहा जा सकता है।

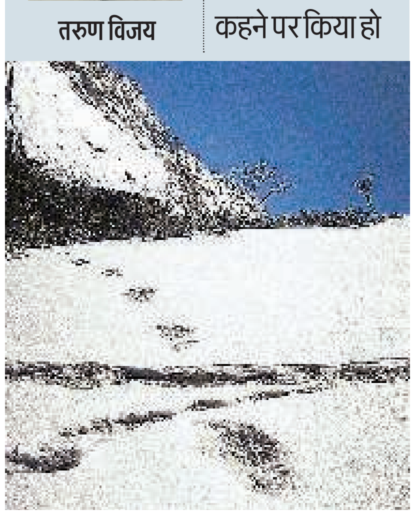

बीते दिनों सेना के एक पर्वतारोही दल ने अपने खोजी अभियान में बर्फ पर बड़े-बड़े पैरों के निशान देखे तो स्वाभाविक ही था कि वे वैज्ञानिकों के सामने इस तथ्य को रखते हुए पूछते कि क्या ये पदचिन्ह येती के हो सकते हैं? येती के विषय में मेरा कॉलेज के समय से अध्ययन रहा है। तिब्बत के गवर्नर से कहकर मैं दो बार दक्षिण पश्चिम तिब्बत के क्षेत्र में विश्व के महान चमत्कारी बौद्ध योगी मिलारेप्पा की गुफा तक पहुंचा और वहां श्वेत तारा, नील तारा और डाकिनी देवियों के क्षेत्र में येती के संबंध में व्याप्त विश्वास और कथा सूत्रों का संग्रह किया। येती के विषय में प्रचुर साहित्य उपलब्ध है। यह मान्यता बहुत पुरानी है कि हिम मानव यानी येती हिमालय की ऊंची बर्फीली चोटियों के बीच कहीं रहते हैं। कलिमपोंग में 1940 और 1950 के दशक में वहां के समाचार पत्रों में येती के बारे में अनेक लेख-समाचार प्रकाशित हुए। 1960 में एवरेस्ट विजेता सर एडमंड हिलेरी ने येती के एक कपाल को लेकर खुमजुंग बौद्ध मठ के प्रमुख लामा के साथ येती की खोज का अभियान छेड़ा था और बाद में उस कपाल को लंदन ले जाकर उसकी वैज्ञानिक जांच कराई थी। कलिमपोंग से प्रकाशित 8 और 15 फरवरी 1959 के हिमालयन टाइम्स समाचार पत्र में येती के करीब रहकर आए लोगों और येती द्वारा गांव से उठाकर ले जाए गए लोगों के अनुभव प्रकाशित हुए। ज्यादातर रपटें ब्रिटेन और अमेरिका में रहने वाले पश्चिमी शिक्षा पाए यात्रियों ने लिखीं। रूसी अखबार इजेविस्तिया ने येती के माध्यम से नेपाल-तिब्बत सीमा पर अभियान कर रहे टाम सलिक पर अमेरिकी जासूस होने का आरोप लगाया जो 12 मई 1957 के हिमालयन टाइम्स में छपा। येती अभियान के बहाने जासूसी के इतने अधिक आरोप लगे कि जून 1957 में नेपाल सरकार ने येती अभियान के तौर-तरीकों के बारे में एक विस्तृत नियमावली जारी की। 1960 में सर एडमंड हिलेरी द्वारा नारायण हेटटी महल में तत्कालीन महाराजाधिराज महेंद्र वीर विक्रम शाहदेव को येती का सिर भेंट किए जाने का समाचार भी प्रकाशित हुआ था। स्विस, जर्मन और स्थानीय शेरपाओं के हजारों वृत्तों में येती का वर्णन मिलता है, लेकिन भारतीय सेना के पर्वतारोही दल ने जब येती का जिक्र किया तो कई सेक्युलर बुद्धिजीवियों ने चीन के उन समाचार पत्रों को प्रमुखता से उद्धृत किया जिनमें भारतीय सैन्य दल का मखौल उड़ाया गया था। दरअसल ये वे लोग हैं जो विदेशी अखबारों में भारतीय सेना पर अनुचित टिप्पणी को महत्व देने का कोई मौका नहीं छोड़ते। वे इन टिप्पणियों को ऐसे लपक लेते हैं मानो वह ईश्वरीय प्रसाद हो। सोशल मीडिया पर इन सेक्युलर तत्वों ने येती का सहारा लेकर मोदी और सेना पर हमले शुरू कर दिए। किसी ने लिखा कि मोदी येती का मंदिर बनाएंगे तो किसी अन्य ने लिखा कि यह बेहद शर्मनाक है कि भारतीय सेना अफवाहें फैला रही हैं। एक ने यह भी लिखा कि भारतीय सेना को विज्ञान की नवीनतम खोजों की कोई जानकारी ही नहीं होती।

भारतीय सेना अगर दुश्मन के घर में घुसकर हमला करे तो यही लोग उस पर शक करते हैं। वह कोई विशेष खोज करे तो उसका मजाक उड़ाते हैं और सेना के बहाने प्रधानमंत्री पर ताने मारने का भी काम करते हैं। इस पर बहस हो सकती है कि सेना के दावे का क्या आधार है और वह कैसे इस नतीजे पर पहुंची कि पदचिन्ह येती के हैं, लेकिन आखिर उसका मजाक उड़ाना कहां तक उचित है?

(लेखक राज्यसभा के पूर्व सदस्य एवं वरिष्ठ स्तंभकार हैं)

response@jagran.com

ऊर्जा

समन्वय

समन्वय आत्मा की भाषा है। आज मनुष्य अंतरात्मा की आवाज सुनने को तैयार नहीं है। वह भीतर से टूट रहा है और बाहर से बिखर रहा है। मानव के अस्तित्व की समस्याएं सार रूप में सर्वांग समन्वय से संबंधित समस्याएं हैं। समन्वय की पहली समस्या व्यक्ति के भीतर ज्ञान, भाव और कर्म के मध्य संतुलन स्थापित करने से संबंधित है। न तो ज्ञान के अनुकूल भाव है और न ही भाव के अनुकूल कर्म। कोरा ज्ञान पांडित्य प्रदर्शन है, कोरी भावुकता मूर्खता है और कोरा कर्मकांड पाखंड है। ज्ञान का जीवन में उतरना ही सदाचार है। बार-बार सत्कर्म करना ही चरित्र है।

समन्वय की दूसरी समस्या व्यक्ति-व्यक्ति के बीच तालमेल कायम करने से संबंधित है। इस समस्या का समाधान वेदांत के इस तत्वज्ञान में है कि सब आत्मवत् हैं। जब एक ही आत्मा सब के भीतर है तो परस्पर द्वेष क्यों? ऊंच-नीच या छुआछूत का भेदभाव क्यों? जब सब एक ही आत्मा के प्रसार हैं, तब जगत में किसी को तुच्छ नहीं कहा जा सकता। तीसरी समस्या समष्टि के साथ समन्वय की समस्या है। इस समस्या का हल तभी निकलेगा, जब हर व्यक्ति स्वार्थ और वासना के घेरे से ऊपर उठकर समाज की धरोहर बन जाएगा। आशय यह है कि उसके 'स्व' का समाजीकरण हो जाएगा। वह समाज के लिए जिएगा और समाज के लिए मरेगा।

समन्वय से संबंधित चौथी समस्या विभिन्न समूहों के मध्य संतुलन स्थापित करने से जुड़ी है। मजहबी उन्माद, जातीय विद्वेष और वर्ग संघर्ष विभिन्न वर्गों के बीच संतुलन स्थापित न होने के दुष्परिणाम हैं। इस समस्या का समाधान वेदांत के इस सूत्र में तलाशना है कि 'एकं सद्विप्रा बहुधा वदंति।' यानी सभी धर्म एक ही सत्य के रंग-बिरंगे फूल हैं। पांचवीं समस्या समष्टि के साथ ईश्वर के समन्वय से संबंधित है। सत्य को ही ईश्वर मान लेने से यह समस्या मिट जाती है। आखिर सत्य का आदर तो सभी करते हैं। चाहे राम कहो या रहीम मतलब तो खुदा की चाह से है। जब सृष्टि के कण-कण में एक ही ईश्वर रम रहा है तो कोई भी पंथ निकृष्ट नहीं है। अपनी हृदय-दृष्टि खोलो, सब में ईश्वर की छवि दिखाई देगी। ईश्वर से साक्षात्कार करने का यह पहला आधार है। हृदय के चक्षु खोले बिना परमपिता का आभास होना असंभव है।

डॉ. दुर्गादत्त पांडेय

लोकतंत्र का प्रतीक

फिर से

मेरी अंगुली पर लगी स्याही मेरा अभिमान है, मेरा स्वाभिमान है, मेरी स्वतंत्रता है और मेरा लोकतंत्र है

एक जमाना था जब अंगुली पर स्याही का निशान लगने पर मिटाने की जल्दी रहती थी, लेकिन एक जमाना यह भी है कि अंगुली मचल रही है, चुनावी स्याही का निशान लगाने को! देश में लोकतंत्र है, इसी बात का तो सुबूत है यह निशान! सदियों से मानवता लोकतंत्र के लिए तड़पी है, कभी राजशाही तो कभी तानाशाही और कभी गुलामी! अब जाकर कहीं लोकतंत्र आया है। विवाहित महिलाओं के पास सिंदूर होता है, बताने को की हम विवाहित हैं और अंगुली की स्याही बताती है कि हम न केवल स्वतंत्र हैं, अपितु हमारे देश में लोकतंत्र है। हमारे पास भी वे सारे ही अधिकार हैं जो कभी एक राजा के पास हुआ करते थे। जब भगवान के मंदिर जाते हैं तो माथे पर कुमकुम जरूर लगाते हैं, बाहर निकलकर हमारा कुमकुम ही इतराकर बता देता है कि हम मंदिर गए थे। बस ऐसी ही चुनाव की स्याही है, जो हमारे हाथ में लगती है और इतराती है। कभी मंदिर जाने का अधिकार छीनकर देख लो, मन कैसे छटपटाता है? राजा रवि वर्मा बहुत बड़े चित्रकार हुए, उन्होंने अपने चित्रों की छपाई करा दी। करोड़ों ऐसे लोग थे जिन्हें मंदिर में प्रवेश नहीं मिला था। उन लोगों ने पहली बार उस चित्र के माध्यम से भगवान को देखा और अपने घर में लगाकर पूजा की। लोग भाव विह्वल हो रहे थे, अपने जीवन को धन्य मान रहे थे। ऐसे ही जब पहली बार लोगों को राजा की जगह अपना नेता चुनने का अवसर मिला तो लोग भाव विह्वल हो गए थे। वे अपनी अंगुली पर लगी स्याही को देख रहे थे, उसे चूम रहे थे और लोगों को दिखा रहे थे कि देखो हमारे पास भी अब अधिकार है।

जरा सोचिए, यदि मंदिर प्रवेश का अधिकार सभी को होता तो क्या राजा रवि वर्मा की पेंटिंग को लोग खरीदते? क्या उन पेंटिंग को अपने घर में लगाकर पूजते? नहीं कभी नहीं करते। सभी को अधिकार मिलते ही अधिकार की चाहत ही समाप्त हो जाती है। जैसे लोकतंत्र मिला और सभी को वोट का अधिकार मिला तो चाहत ही समाप्त हो गई। कुछ लोग बेपरवाह हो गए। जैसे मंदिर में नहीं जाना फैशन बन गया है वैसे ही वोट नहीं डालना भी फैशन बन गया है। मंदिर से दूर हो गए, भगवान से दूर हो गए। ऐसे ही वोट डालने में हुआ। वोट नहीं डालना फैशन बन गया, बड़ी ठसक से कहते हैं कि हम वोट नहीं डालते!

स्वतंत्रता और परतंत्रता का जिन्हें अंतर नहीं पता वे वोट देने का मखौल उड़ाते हैं, नोटा दबाने की बात करते हैं। कैसा भी नेता है, तुम्हारे देश का और लोकतंत्र का प्रहरी है, लेकिन यदि लोकतंत्र ही नहीं रहेगा तो चाहे ईस्ट इंडिया कंपनी वापस आए या फिर मुगल साम्राज्य? लेकिन कुछ लोगों को अपनी अंगुली पर स्याही का निशान फबता नहीं है, लोकतंत्र का निशान उन्हें जंचता नहीं है, लेकिन हमारे लिए तो यह स्याही अमूल्य स्याही है। स्याही को भगवान को भी दिखाएंगे और कहेंगे कि हे भगवान! हमें और हमारी पीढ़ियों को कभी भी इस स्याही से वंचित मत करना। स्याही ही लोकतंत्र का प्रतीक है। मेरी अंगुली पर लगी स्याही मेरा अभिमान है, मेरा स्वाभिमान है, मेरी स्वतंत्रता है और मेरा लोकतंत्र है। जो भी इस स्याही की इज्जत नहीं करता वह हमारे स्वाभिमान का हंता है, हमारे लोकतंत्र का नाशक है। प्रभु इनको सद्बुद्धि देना और हमारी रक्षा करना।

(अजित गुप्ता का कोना ब्लॉग से साभार)

मेलबाक्स

देश को सुरक्षित जीवन और विकास चाहिए

एक ही मुद्दा-एक ही नाम शीर्षक से लिखे अपने लेख में प्रो. निरंजन कुमार का भारत की राष्ट्रीय राजनीति में धूमकेतु की तरह उभरने वाले नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता को उनका 'पर्सनैलिटी कल्ट' बताना बिल्कुल सही है। 2014 का आम चुनाव मोदी के इसी 'पर्सनैलिटी कल्ट' की अग्नि परीक्षा थी, जिस पर वह खरे उतरे, लेकिन अब 2019 में देश की जनता मोदी के पांच वर्षीय कृतित्व को सामने रखकर अपना फैसला देगी। ऐसे में धरातल पर दिखने वाली लोकहितैषी विकास योजनाएं मोदी शासन को परखने का पैमाना बन रही हैं। ठीक इसके विपरीत 60 वर्षों तक देश को शासित करने वाली कांग्रेस और उसी सोच की राजनीति करने वाले सपा, बसपा, राजद, टीएमसी जैसे अनेक क्षेत्रीय राजनीतिक दल केवल पांच वर्षों के अल्पकाल में हुए विकास कार्यों और वैश्विक स्तर पर बढ़ती भारत की साख से हतप्रभ होकर 'मोदी हटाओ' के एकसूत्रीय कार्यक्रम के तहत अपनी एकजुटता का प्रदर्शन करते दिखाई दे रहे हैं। लेकिन देश की जनता इन सबकी 'अपनी-अपनी ढपली, अपना-अपना राग' की स्वार्थपरक राजनीति को बखूबी समझ रही है। इस दृष्टि से विपक्ष की यह खोखली एकजुटता 2019 के आम चुनाव को प्रभावित कर पाएगी, इसमें संदेह है। आज मोदी शासन की वैश्विक कूटनीति का ही सुपरिणाम है कि संयुक्त राष्ट्र ने कुख्यात आतंकवादी मसूद अजहर को अंतरराष्ट्रीय आतंकवादी घोषित कर उस पर विश्वव्यापी प्रतिबंध लगा दिए हैं। अमानवीय और हिंसक आतंकवाद पर मोदी सरकार की जीरो टॉलरेंस की नीति के चलते आम नागरिकों का जीवन आतंकी हमलों से सुरक्षित हुआ है। उड़ी और पुलवामा आतंकी हमले के बाद भारत की ओर से की जाने वाली सर्जिकल स्ट्राइक ने पाकिस्तान को बिना युद्ध किए परास्त कर दिया है। मोदी शासन की ये उपलब्धियां आज विपक्ष का पसीना निकाल रही हैं। अल्पसंख्यक तुष्टीकरण, भ्रष्टाचार और पाक समर्थित आतंकवाद को नजरंदाज करने वाली राष्ट्रघाती नीतियों की जगह अब इस देश को सुरक्षित जीवन और विकास चाहिए, इस तरह की परिवर्तित सोच मोदी सरकार की राष्ट्रहितैषी नीतियों का ही सुफल है। शायद इसीलिए मोदी इस आम चुनाव के केंद्र में हैं।

डॉ. वीपी पाण्डेय, अलीगढ़

नक्सलवाद का खौफ

पहले छत्तीसगढ़ और अब एक महीने में दूसरी बार महाराष्ट्र के गढ़चिरौली में नक्सलवादी हमला होना दुखद है। इसमें कोई दो राय नहीं कि यह एक सुनियोजित हमला था, क्योंकि सुरक्षा के तहत नक्सल प्रभावित क्षेत्र में पेट्रोलिंग के लिए सभी जवान सरकारी वाहन के बजाय निजी वाहन में सवार होकर गए थे और केवल एक पट्रोल पंप से ही ईंधन डलवाया था। उसके बावजूद नक्सली हमला होना यही दर्शाता है कि इस मुखबरी में अर्बन नक्सलियों का भी हाथ है। उनका मकसद चुनावी माहौल को बिगाड़ना रहा होगा। सरकार को शीघ्र इस नक्सलवाद पर कठोरतम कार्रवाई करनी चाहिए। उल्लेखनीय है कि सरकार की कड़ी कार्रवाई के कारण ही आज नक्सलवाद 161 जिलों से सिमट कर केवल 90 जिलों में रह गया है। लेकिन यह भी समझ से परे है कि इन नक्सलवादियों के पास पैसा, गोला बारूद और अत्याधुनिक हथियार कैसे आ जाते हैं? कौन इनकी वित्तीय मदद करता है? और कौन इनके लिए मुखबरी? सरकार को अपने खुफिया तंत्र को और मजबूत कर नक्सलियों की गतिविधियों पर नजर रखने की जरूरत है। उनसे सीधी लड़ाई के बजाय उनके संसाधनों को कमजोर किया जाना चाहिए। इससे वे खुद कमजोर हो जाएंगे। ऐसे में कोई हमला करने में खुद ही असमर्थ पाएंगे। तब सुरक्षा बलों को उन पर काबू पाना आसान हो जाएगा।

दीपक गौतम, सोनीपत

संविधान की मूलभावना

चुनाव में लगभग सभी दल सांप्रदायिक एवं जातिवाद पर आधारित राजनीति को प्रश्रय देते हैं। प्रत्येक दल किसी भी व्यक्ति को टिकट देने के पूर्व उस क्षेत्र विशेष में कितने हिंदू हैं, कितने मुस्लिम हैं, कितने पिछड़े हैं, कितने दलित हैं, कितने ब्राह्मण, ठाकुर, कायस्थ या वैश्य हैं, आदि की संख्या पता करता है और उसमें गुणा भाग कर जीतने की संभावना वाले जाति समीकरण के अनुकूल टिकट वितरण करता है। यह संविधान की मूल भावना के विपरीत है। किसी भी क्षेत्र की जनसंख्या का विवरण धर्म या जाति के आधार पर किसी को उपलब्ध नहीं कराया जाना चाहिए।

dharmendranath.rastogi@gmail.com

इस स्तंभ में किसी भी विषय पर राय व्यक्त करने अथवा दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण पर प्रतिक्रिया व्यक्त करने के लिए पाठकगण सादर आमंत्रित हैं। आप हमें पत्र भेजने के साथ ई-मेल भी कर सकते हैं।

अपने पत्र इस पते पर भेजें :
दैनिक जागरण, राष्ट्रीय संस्करण,
डी-210-211, सेक्टर-63, नोएडा
ई-मेल: mailbox@jagran.com

संस्थापक-स्व. पूर्णचन्द्र गुप्त. पूर्व प्रधान संपादक-स्व.नरेन्द्र मोहन. संपादकीय निदेशक-महेन्द्र मोहन गुप्त. प्रधान संपादक-संजय गुप्त, जागरण प्रकाशन लि. के लिए: नीतेन्द्र श्रीवास्तव द्वारा 501, आई.एन.एस. बिल्डिंग,रफी मार्ग, नई दिल्ली से प्रकाशित और उन्हीं के द्वारा डी-210, 211, सेक्टर-63 नोएडा से मुद्रित, संपादक (राष्ट्रीय संस्करण) -विष्णु प्रकाश त्रिपाठी*
दूरभाष : नई दिल्ली कार्यालय : 23359961-62, नोएडा कार्यालय : 0120-3915800, E-mail: delhi@nda.jagran.com, R.N.I. No. DELHIN/2017/74721 * इस अंक में प्रकाशित समस्त समाचारों के चयन एवं संपादन हेतु पी.आर.बी. एक्ट के अंतर्गत उत्तरदायी। समस्त विवाद दिल्ली न्यायालय के अधीन ही होंगे। हवाई शुल्क अतिरिक्त।